चार कंपनियों को मिली बैटरी भंडारण की मंजूरी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने उन्नत रसायन सेल यानि एसीसी बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए चार सफल बोलीदाताओं को 50 गीगावाट बैटरी क्षमता के लिए आवंटन किया है। सरकार की तरफ से दी गई जाानकारी के मुताबिक विनिर्माण केंद्र दो वर्ष के भीतर स्थापित किए जाएंगे।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने बताया है कि देश में एक अनुकूल नियामक ढांचे के कारण हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में वृद्धि से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में जो भी कंपनियां इस दिशा में उत्पादन के लिए आगे आ रही है उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, ऑटो उद्योग का इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) परिक्षेत्र में विकास निश्चित रूप से हमें सीओपी 26 में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंचतंत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही भारतीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा।

इस योजना में जिन कंपनियों का चयन किया गया है, उसमें रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हुंडई ग्लोबल मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। इन कंपनियों को भारत में स्थानीय बैटरी सेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के तहत 18,100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय, केंद्रीय मंत्री

ईवी को अपनाने में मदद मिलेगी

मंत्रालय के मुताबिक, बोलीदाताओं का अंतिम मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत-आधारित चयन तंत्र के अनुसार किया गया था। उनकी तकनीक और वित्तीय स्कोर के संयुक्त आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया था। एसीसी के लिए इस पीएलआई स्कीम और मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पहले से ही चल रही पीएलआई योजना और फेम से भारत को पारंपरिक परिवहन प्रणाली के स्थान पर पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ, टिकाऊ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी।